DJ Rashtriya Sanskaran, Delhi, 04/01/2026
Page No: 5, Size: 9.02cm × 25.00cm

महिलाओं के स्मार्टफोन के उपयोग पर पाबंदी पर जालौर के डीएम को नोटिस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : राजस्थान के जालौर जिले में 15 गांवों की महिलाओं के कैमरे वाला स्मार्टफोन उपयोग करने पर पाबंदी के पंचायत के आदेश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संबंध में मिली शिकायत पर जालौर के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है। निर्देश दिया है कि वह शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करके दो सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को दें।

राजस्थान के जालौर जिले की गाजीपुर गांव में हुई चौधरी समाज की सुंधामाता पट्टी की पंचायत ने 15 गांवों की महिलाओं के लिए कैमरे वाले स्मार्टफोन के उपयोग पर पाबंदी लगाई है। पाबंदी का यह नियम 26 जनवरी से लागू होना है। पंचायत के फैसले के मुताबिक महिलाएं अब स्मार्टफोन की जगह की-पैड फोन का ही उपयोग कर सकेंगी। महिलाओं के शादी समारोह आदि सामाजिक कार्यक्रमों और पड़ोसी के घर जाते समय भी मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है।

Jansatta, Delhi, 04/01/2026
Page No: 2, Size: 12.22cm × 8.73cm

लेह के उपायुक्त, पुलिस अधिकारियों को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 जनवरी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इन आरोपों को लेकर लेह प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को एक नोटिस जारी किया है कि दिसंबर के अंत में अपने घर से लापता हुई बौद्ध समुदाय की एक नाबालिग आदिवासी लड़की बाद में 'श्रीनगर में एक मुस्लिम लड़के के साथ मिली।'

नाबालिग लद्दाखी लड़की का मामला।

दो जनवरी की मामले की कार्यवाही में कहा गया है कि लड़की फिलहाल बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की देखरेख में है और मानसिक आघात का सामना कर रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल के निवासी शिकायतकर्ता सागर भंते के अनुसार, शिकायत में कहा गया है कि 26 दिसंबर को आदिवासी बौद्ध समुदाय से संबंध रखने वाली एक नाबालिग लद्दाखी लड़की अपने घर से लापता हो गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके परिवार ने तुरंत खलत्से थाने में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के दौरान, उक्त लड़की श्रीनगर में एक मुस्लिम लड़के के साथ पाई गई। कार्यवाही में कहा गया है कि फिलहाल, लड़की बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की देखरेख में है, और वह मानसिक आघात का सामना कर रही है।

शिकायतकर्ता ने आयोग से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और 'अपराध में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच, पीड़िता लड़की और उसके परिवार के लिए न्याय, सुरक्षा, काउंसलिंग, चिकित्सा, मानसिक और कानूनी सहायता की मांग की।'

Daily Excelsior, Jammu, 04/01/2026
Page No: 1, Size: 16.51cm × 12.86cm

NHRC issues notice to DC Leh

NEW DELHI, Jan 3:

The NHRC has issued a notice to the Leh civil administration and its police authorities over charges that a minor Ladakhi girl belonging to a tribal Buddhist community who had gone missing from her home late December, was subsequently "found in Srinagar with a Muslim boy," according to the proceedings of the case.

Presently, the girl is under

(Contd on page 4 Col 1)

NHRC issues notice to DC Leh

the supervision of a Child Welfare Committee (CWC) and is suffering from "mental trauma," the proceedings dated January 2 said.

The complainant is Sagar Bhante, from Bhopal in Madhya Pradesh, it said.

"The complainant alleged that on December 26, a minor Khalatse Ladakhi girl belonging to a tribal Buddhist community went missing from her home. The complainant further alleged that her family immediately lodged a missing complaint with the PS Khalatse, FIR No.39/2025 dated 28.12.2025, u/s 137(2) BNS and under the POCSO Act. During the police investigation, the said girl was found in Srinagar with a Muslim boy," it said.

"Presently, the girl is under the supervision of CWC, and she is now in mental trauma," the proceedings said.

The complainant had sought the intervention of the commission and requested an "impartial investigation into the role of other individuals involved in the crime, justice for the victim girl and her family, protection, counselling with medical, psychological, and legal assistance.

"Due to social pressure at the local level, this sensitive case is not receiving the seriousness it warrants. A detailed action-taken report should be sought from the police and the administration, in accordance with the law," it said.

The allegations made in the complaint prima facie seem to be violations of the human rights of the victim, the rights panel said.

A bench of the National Human Rights Commission (NHRC), presided by its member Priyank Kanoongo, has taken cognisance under section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

"The Registry is directed to issue a notice to the DC (Deputy Commissioner), Leh and the SSP/DIG, Leh, Ladakh, with directions to get the allegations made in the complaint inquired into and to submit an action taken report within seven days for perusal of the Commission," it adds. (PTI)

Statesman, Kolkata, 04/01/2026
Page No: 3, Size: 25.96cm × 14.76cm

NHRC sets 4-week deadline for W. Burdwan District Magistrate, police on silicosis report

DEBAJYOTI CHAKRABORTY
Durgapur, 3 January

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of the silicosis issue in the Dendua region of Salanpur block and has issued reminders to the District Magistrate (DM) of West Burdwan, S. Ponnambalam, and the Commissioner of Police (CP) of the Asansol-Durgapur Police Commissionerate (ADPC), Sunil Kumar Choudhary, seeking an action taken report (ATR) against polluting industries operating in the area.

The NHRC has made it clear that if the ATR is not submitted within four weeks, it will be compelled to exercise its powers under the Protection of Human Rights Act, 1993. A copy of the reminder has also been sent to the state Chief Secretary, Nandini Chakravorty, underscoring the seriousness of the matter.

Silicosis is reportedly spreading rapidly in the Salanpur block of the Asansol Sadar sub-division in West Burdwan district. It has been alleged that neither the police nor the administration took adequate action earlier. Local social worker Amarendra Mahato had approached the NHRC, alleging that silicosis patients were being incorrectly treated as tuberculosis cases under the DOTS programme and that factory managements should be held responsible for the victims.

Earlier, on 28 October, 2024, the NHRC had written to the West Burdwan DM and the ADPC Commissioner seeking a report within eight weeks following a complaint by a local teacher, Amarnath Mahato. The complaint alleged that stone and silica crushing units in the area were causing the spread of silicosis and that several labourers had already died.

Subsequently, on 17 November, 2024, a general diary (GD) entry (No. 513) was registered at Salanpur police station, directing verification of industrial units located in the Dendua area. The District Industries Centre and the West Bengal Pollution Control Board were asked to conduct physical verification of the factories, and the information was shared with local residents.

The NHRC had also sought the deployment of a technical expert team to measure silicon metalloid emissions from the factories, citing serious environmental and public health concerns. However, as the expert team's report is still awaited, the Commission has issued fresh reminders, granting a final four-week deadline for submission of the ATR.

The NHRC has warned that failure to submit the required investigation and pollution reports within this period will invite legal action under the Protection of Human Rights Act, 1993.

In 2025, two residents of Salanpur block reportedly died due to silicosis, while several labourers have been diagnosed with the disease by the Medical Board constituted by the Chief Medical Officer of Health (CMOH), West Burdwan, and Asansol District Hospital following health screenings.

No official response has so far been received from either the West Burdwan District Magistrate or the Commissioner of Police, ADPC, on the issue.

Jansatta, Lucknow, 04/01/2026
Page No: 2, Size: 15.13cm × 10.95cm

लेह के उपायुक्त, पुलिस अधिकारियों को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 जनवरी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इन आरोपों को लेकर लेह प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को एक नोटिस जारी किया है कि दिसंबर के अंत में अपने घर से लापता हुई बौद्ध समुदाय की एक नाबालिग आदिवासी लड़की बाद में 'श्रीनगर में एक मुस्लिम लड़के के साथ मिली।'

नाबालिग लद्दाखी लड़की का मामला।

दो जनवरी की मामले की कार्यवाही में कहा गया है कि लड़की फिलहाल बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की देखरेख में है और मानसिक आघात का सामना कर रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल के निवासी शिकायतकर्ता सागर भंते के अनुसार, शिकायत में कहा गया है कि 26 दिसंबर को आदिवासी बौद्ध समुदाय से संबंध रखने वाली एक नाबालिग लद्दाखी लड़की अपने घर से लापता हो गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके परिवार ने तुरंत खलत्से थाने में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के दौरान, उक्त लड़की श्रीनगर में एक मुस्लिम लड़के के साथ पाई गई। कार्यवाही में कहा गया है कि फिलहाल, लड़की बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की देखरेख में है, और वह मानसिक आघात का सामना कर रही है।

शिकायतकर्ता ने आयोग से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और 'अपराध में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच, पीड़िता लड़की और उसके परिवार के लिए न्याय, सुरक्षा, काउंसलिंग, चिकित्सा, मानसिक और कानूनी सहायता की मांग की।'

Amar Ujala, Jammu, 04/01/2026
Page No: 7, Size: 15.77cm × 11.27cm

नाबालिग बौद्ध लड़की के लापता होने के मामले में लेह प्रशासन व पुलिस को नोटिस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

लेह। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने लेह में एक नाबालिग बौद्ध लड़की के लापता होने और बाद में श्रीनगर में पाए जाने के संवेदनशील मामले में लेह के नागरिक प्रशासन और पुलिस को नोटिस जारी कर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने माना कि लगे आरोप प्रथम दृष्टया लड़की के मानव अधिकारों के उल्लंघन का संकेत देते हैं।

आयोग की ओर से 2 जनवरी को दर्ज की गई कार्यवाही के अनुसार उपायुक्त लेह व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /डीआईजी लेह को सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, पुलिस प्रमुख श्रीराम आर व उपायुक्त रोमिल सिंह डोंक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें अभी तक औपचारिक नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी सागर भंते द्वारा दायर शिकायत के अनुसार 26 दिसंबर को लेह के खाल्त्सी उप-मंडल की रहने वाली नाबालिग लड़की अपने घर से लापता हो गई थी।

परिजन की शिकायत पर पुलिस ने 28 दिसंबर को गुमशुदगी और पॉक्सो अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की। जांच में लड़की को श्रीनगर में एक मुस्लिम युवक के साथ पाया गया। फिलहाल लड़की बाल कल्याण समिति की निगरानी में है। शिकायतकर्ता ने मामले में सभी संभावित भूमिकाओं की निष्पक्ष जांच, पीड़िता और परिवार को न्याय, तथा लड़की को सुरक्षा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता मुहैया कराने की मांग की है। साथ ही स्थानीय स्तर पर सामाजिक दबाव के चलते मामले की गंभीरता से निपटे न जाने का भी आरोप लगाया गया है।

आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। यह मामला बाल संरक्षण और मानवाधिकार मानकों के कड़ाई से पालन की मांग के केंद्र में बना हुआ है। संवाद

JANSATTA, Chandigarh, 04/01/2026
Page No: 02, Size: 15.82cm × 12.57cm

लेह के उपायुक्त, पुलिस अधिकारियों को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 3 जनवरी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इन आरोपों को लेकर लेह प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को एक नोटिस जारी किया है कि दिसंबर के अंत में अपने घर से लापता हुई बौद्ध समुदाय की एक नाबालिग आदिवासी लड़की बाद में 'श्रीनगर में एक मुस्लिम लड़के के साथ मिली।'

नाबालिग लद्दाखी लड़की का मामला।

दो जनवरी की मामले की कार्यवाही में कहा गया है कि लड़की फिलहाल बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की देखरेख में है और मानसिक आघात का सामना कर रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल के निवासी शिकायतकर्ता सागर भंते के अनुसार, शिकायत में कहा गया है कि 26 दिसंबर को आदिवासी बौद्ध समुदाय से संबंध रखने वाली एक नाबालिग लद्दाखी लड़की अपने घर से लापता हो गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके परिवार ने तुरंत खलत्से थाने में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के दौरान, उक्त लड़की श्रीनगर में एक मुस्लिम लड़के के साथ पाई गई। कार्यवाही में कहा गया है कि फिलहाल, लड़की बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की देखरेख में है, और वह मानसिक आघात का सामना कर रही है।

शिकायतकर्ता ने आयोग से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और 'अपराध में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच, पीड़िता लड़की और उसके परिवार के लिए न्याय, सुरक्षा, काउंसलिंग, चिकित्सा, मानसिक और कानूनी सहायता की मांग की।'

Punjab Kesari, Jalandhar, 04/01/2026
Page No: 07, Size: 9.50cm × 12.17cm

पंजाब केसरी
SUN,04 JANUARY 2026
EDITION: JODHPUR , PAGE NO. 7

पानी के गड्ढे में गिरे 2 के मासूम की मौत

खेलते समय हादसा, ईंट-भट्ठे पर काम कर रहे थे माता-पिता

धौलपुर, 3 जनवरी (संजय जगरिया) : जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के कुम्हेरी गांव में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में दो वर्षीय बालक की पानी से भरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। घटना के समय मासूम पास में खेल रहा था, जबकि उसके माता-पिता ईंट-भट्ठे पर मजदूरी में व्यस्त थे।

मृतक की पहचान वीर पुत्र गंगाराम पटेल के रूप में हुई है। परिजन मूल रूप से रायगढ़ जिले के बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के निवासी हैं और काफी समय से कुम्हेरी गांव में रहकर मजदूरी कर रहे थे। खेलते-खेलते वीर पास बने पानी से भरे गड्ढे के पास पहुंच गया और उसमें गिरकर अचेत हो गया।

कुछ देर बाद परिजनों को जानकारी मिली, जिसके बाद वे बच्चे को तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस के अनुसार परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।

Bhaskar English, Online News, 04/01/2026

Source:
https://www.bhaskarenglish.in/local/gujarat/ahmedabad/news/nhrc-issues-notice-to-ahmedabad-collector-over-vendor-rights-seeks-report-on-alleged-assault-at-vegetable-market-136845675.html

NHRC issues notice to Ahmedabad Collector over vendor rights:NHRC issues notice to Ahmedabad Collector over alleged assault at vegetable market; hawkers demand return of seized goods

Ahmedabad11 hours ago Author: Aziz Cutleriwala
The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a reminder notice to Ahmedabad Collector Sujeet Kumar, seeking an action taken report (ATR) in connection with allegations of human rights violations against street vendors at the Jodhpur vegetable market in the city.
NHRC's reminder notice to Ahmedabad Collector
The matter pertains to a confrontation between vegetable vendors operating in the Jodhpur area and officials of the South West Zone of the Ahmedabad Municipal Corporation (AMC). Taking cognisance of the complaint, the NHRC observed that the vendors' constitutional and human rights appeared to have been violated and that urgent action was warranted.
According to the reminder notice, the Commission had earlier, on 30 July, 2025, sought an ATR from the Ahmedabad Collector. However, no report has been received so far.
The Commission stated that the matter was reviewed again on 1 January, following which the Collector has been directed to submit a complete or additional report by 25 January, for further consideration.
AMC officials' altercation with vegetable vendors
The case originates from a complaint received by the NHRC on 28 January, 2025, filed by social activist Kantilal Parmar on behalf of over 200 street vendors. The complaint alleged that AMC officials carried out physical assaults on vendors, illegally seized their goods and handcarts, and destroyed vegetables and other produce, severely impacting their daily livelihood.
Parmar said the vendors have raised several key demands, including registration of FIRs and departmental inquiries against responsible AMC officials, strict implementation of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, immediate allotment of vending spaces to more than 200 long-time vendors, and the return of confiscated goods and mobile phones.

Clarion India, Online News, 04/01/2026

Source: https://clarionindia.net/judicial-probe-urged-into-death-of-dalit-student-in-himachal-pradeshs-college/

Judicial Probe Urged into Death of Dalit Student in Himachal Pradesh's College

Team Clarion | Date: January 3, 2026

Scheduled Caste student Pallavi (19) was allegedly harassed and intimidated over an extended period by three senior students and a professor

DHARAMSHALA — The death of Pallavi, a 19-year-old Dalit student of Government Degree College, in the Himachal Pradesh town of Dharamshala, has sparked serious allegations of caste- and gender-based violence and institutional failure, with rights organisations demanding swift arrests, resignations, and an independent judicial inquiry.

In a statement, the Dalit Adivasi Shakti Adhikar Manch (DASAM) and its women's collective, Mahila Kaamkaji Manch (MKM), termed Pallavi's death "tragic and preventable," alleging that she was subjected to sustained ragging, sexual harassment, physical assault, and extreme psychological trauma within the college campus.

According to the complaint filed by Pallavi's father and the FIR registered by the police, Pallavi, a Scheduled Caste student, was allegedly harassed and intimidated over an extended period by three senior students identified as Harshita, Aakriti, and Komolika. The organisations allege that the abuse occurred in public spaces within the institution and was marked by humiliation and violence rooted in caste discrimination.

The FIR also names Prof Ashok Kumar, a faculty member of the college, who has been accused of sexually inappropriate behaviour towards the student. Rights groups say the allegations attract provisions of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989, which specifically recognise the heightened vulnerability of Dalit women to sexual abuse by persons in positions of authority.

In addition to the Atrocities Act, offences have reportedly been registered under the Bharatiya Nyaya Sanhita, including sexual harassment, causing hurt, and criminal intimidation. Activists have urged investigators to apply provisions mandating enhanced punishment where crimes are committed against members of Scheduled Castes with knowledge of their caste identity.

DASAM and MKM also pointed to Pallavi's repeated hospitalisations and severe mental distress prior to her death, alleging a complete failure by the college to provide counselling, safety measures, or any trauma-informed response. They said this amounted to a violation of the Mental Healthcare Act, 2017, and of the student's fundamental right to life with dignity under Article 21 of the Constitution.

Holding the college administration accountable, the organisations demanded action against officials for neglect of duty under the SC/ST Act. They also asserted that Pallavi's family is entitled to protection, relief, and compensation under the law.

The case has further raised concerns about the enforcement of the Himachal Pradesh Educational Institutions (Prohibition of Ragging) Act, 2009, and the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. Activists argue that institutional mechanisms meant to prevent ragging and sexual harassment failed to safeguard a Dalit woman student.

Among their demands, the organisations have called for the immediate arrest of all accused persons, noting that anticipatory bail is barred in cases registered under the SC/ST Act. They have also sought the resignation of the college principal and the Himachal Pradesh education minister, termination of the accused professor, rustication of the students named in the FIR, and independent inquiries by the National Human Rights Commission and the National Commission for Women.

Describing the incident as a systemic crisis rather than an isolated tragedy, DASAM warned that such cases reinforce fear and exclusion among Dalit women seeking higher education.

Source: https://connectgujarat.com/news/indore-water-tragedy-contaminated-supply-claims-16-lives-including-infants-and-elderly-10968658

Indore Water Tragedy: Contaminated Supply Claims 16 Lives, Including Infants and Elderly

Public Health Tragedy in Indore: Contaminated Water Claims 16 Lives, Hundreds Hospitalised, Administrative Overhaul Underway.
By Palak Vaghela 03 Jan 2026 in NEWS INDIA
Over 1,400 Residents Fall Sick as Sewage Leak Pollutes Bhagirathpura Drinking Water.
A severe public health crisis has struck Indore's Bhagirathpura area, where contaminated water has claimed 16 lives, including infants and the elderly, and sickened over 1,400 residents. Investigations revealed that sewage from a police outpost toilet leaked into the main drinking water pipeline, contaminating the municipal supply. Around 200 people remain hospitalized, with 32 in intensive care. In response, Chief Minister Mohan Yadav ordered a sweeping administrative overhaul: Kshitij Singhal replaced Dilip Kumar Yadav as IMC Commissioner, while other senior officials were suspended, and the NHRC demanded a detailed report.
Authorities are supplying safe water via tankers, distributing chlorine tablets, disinfecting household tanks, and urging residents to boil water before use. The tragedy has sparked public outrage and criticism of delayed action, highlighting the urgent need for strict monitoring, preventive measures, and rapid emergency response to restore safety and public trust.

Source: https://countercurrents.org/2026/01/how-india-systematically-excludes-its-transgender-population/

How India Systematically Excludes Its Transgender Population

in India by Dr Ranjan Solomon
03/01/2026

India systematically excludes its transgender population through deep-seated social prejudice, leading to familial rejection, educational dropout, economic marginalization (forcing many into begging or sex work), and barriers in healthcare and housing, despite legal recognitions like the NALSA Supreme Court ruling and the Transgender Persons Act. This exclusion stems from a binary view of gender, cultural stigma, and insufficient implementation of inclusive policies, leaving trans individuals vulnerable to violence, discrimination, and poverty, even as laws offer rights.

The Indian Constitution promises equality before law, prohibition of discrimination, and the right to live with dignity. Yet for transgender persons, these guarantees remain largely ornamental. Despite judicial recognition, legislative frameworks, and rhetorical commitments to inclusion, transgender Indians continue to live as citizens without citizenship – visible in census numbers, invisible in policy outcomes, and excluded from the social contract. Their marginalisation is not episodic; it is structural, measurable, and deepened by a stark rural-urban divide.

The evidence is unambiguous. According to the National Human Rights Commission, the literacy rate among transgender persons stands at around 56%, nearly twenty percentage points below the national average. Nearly half of all transgender persons never attend school, while many who do are forced to drop out due to relentless bullying, harassment, and institutional hostility. Schools, instead of functioning as sites of social mobility, become early theatres of exclusion. There are few mechanisms for redress, almost no trained counsellors, and little accountability for teachers or administrators who allow discrimination to flourish.

This educational exclusion feeds directly into economic dispossession. The NHRC's findings are staggering: 92% of transgender persons are denied participation in formal economic activity. Even when educated or skilled, they face routine rejection in hiring, promotions, and workplace retention. As a result, nearly 96% are pushed into informal, precarious, or socially stigmatised work — begging, ceremonial performances, sex work, or daily wage labour. Only about 6% have ever accessed formal employment in the private sector or civil society organisations. Income data reinforces the picture: barely 1% earn more than ₹25,000 per month, placing the overwhelming majority far below any threshold of economic security.

Housing exclusion compounds this precarity. Transgender persons routinely face discrimination by landlords, are denied rental agreements, or are evicted under social pressure. Many are forced into unsafe shared spaces or community enclaves, while others experience homelessness. Despite being officially enumerated in the Census, transgender persons remain absent from housing policy design. Welfare housing schemes rarely specify transgender beneficiaries, and where state initiatives exist, they are small, urban-focused, and poorly implemented.

Health outcomes reveal the human cost of systemic exclusion. HIV prevalence among transgender persons in India is estimated at 3.8%, nearly twenty times the national average. This disparity is not incidental; it reflects forced economic marginalisation, limited access to preventive healthcare, and discrimination within medical institutions themselves. Mental health indicators are even more alarming. Studies suggest that around 31% of transgender persons have attempted suicide, with nearly half doing so before the age of 20. These are not individual pathologies; they are predictable outcomes of sustained social rejection.

Judicially, India has acknowledged these injustices. The Supreme Court's NALSA judgment (2014) recognised transgender persons as a third gender and affirmed their entitlement to fundamental rights, including affirmative action in education and employment. Politically, however, this promise has been diluted. The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019 prohibits discrimination but avoids structural remedies. It offers no reservations, weak penalties for violations, and bureaucratic identity certification processes that many transgender persons experience as humiliating and exclusionary. Enforcement remains negligible, and accountability mechanisms are virtually absent.

Within this already exclusionary landscape, the rural–urban divide intensifies marginalisation. Urban centres, for all their hostility, provide relative anonymity, access to NGOs, healthcare facilities, legal aid, and occasional employment opportunities. Cities host transgender collectives, shelters, and advocacy networks – uneven and insufficient, but real.

Rural India offers almost none of this. Transgender persons in villages face near-total invisibility. Family rejection in rural settings carries harsher consequences, where social surveillance is constant and escape routes limited. Schools, primary health centres, panchayats, and police stations are often deeply uninformed or openly hostile. There are fewer NGOs, no shelters, limited digital access, and virtually no targeted welfare outreach. Documentation barriers – identity cards, residence proof, certificates — further exclude rural transgender persons from schemes that exist largely on paper.

This produces a predictable pattern: distress migration. Transgender persons are pushed out of villages into cities, arriving without education, skills, housing, or safety nets. Their subsequent precarity is then moralised and criminalised, rather than understood as the outcome of systematic exclusion.

Mainstreaming transgender persons cannot be reduced to symbolic inclusion or occasional welfare schemes. It requires constitutional seriousness. First, the state must honour the Supreme Court's mandate by introducing reservations in education and public employment, treating transgender persons as a socially and educationally backward class. Second, anti-discrimination provisions must be enforceable, with clear penalties and independent grievance mechanisms.

Third, economic inclusion must move beyond skill development to guaranteed job placement, supported by incentives and obligations for employers. Fourth, housing schemes — urban and rural — must explicitly include transgender beneficiaries. Fifth, public healthcare must integrate gender-affirming care and mental health services as standard, not optional, provisions.

Equally critical is local governance. Panchayats, ASHA workers, school teachers, police personnel, and district officials must be trained not as benevolent actors, but as constitutional duty-bearers. Without decentralised accountability, rural exclusion will persist regardless of national laws.

Finally, data is political. India cannot govern what it refuses to measure adequately. Comprehensive, disaggregated data on education, employment, housing, health, and rural–urban distribution is essential for evidence-based policymaking and democratic accountability.

Transgender Indians are not seeking charity or exceptional treatment. They are asking for what the Constitution already guarantees: the right to exist without fear, to learn without humiliation, to work with dignity, and to belong as equal citizens. Until those rights are realised — in villages as much as in cities – their exclusion will remain one of the republic's most profound moral and political failures.

Dr. Ranjan Solomon has worked in social justice movements since he was 19 years of age. After an accumulated period of 58 years working with oppressed and marginalized groups locally, nationally, and internationally, he has now turned a researcher-freelance writer focused on questions of global and local/national justice. Since the First Intifada in 1987, Ranjan Solomon has stayed in close solidarity with the Palestinian struggle for freedom from Israeli occupation, and the cruel apartheid system. He has initiated solidarity groups in India, Afro-Asia-Pacific alliance, and at the global level. Ranjan Solomon can be contacted at ranjan.speaks07@gmail.com

This article is part of our Decolonising Bharat series on India's Urban Vs Rural crisis

Source: https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3748603-nhrc-steps-in-on-missing-ladakhi-girl-case-amid-alleged-social-pressures

NHRC Steps in on Missing Ladakhi Girl Case Amid Alleged Social Pressures

The NHRC has issued notices to Leh authorities over the case of a minor Ladakhi girl found in Srinagar with a Muslim boy after going missing. The girl, under Child Welfare supervision, is traumatized. The complainant seeks an impartial investigation and justice amid perceived social pressures hindering the case.

Devdiscourse News Desk |New Delhi |India
Updated:03-01-2026 19:10IST | Created:03-01-2026 19:10IST
The National Human Rights Commission (NHRC) has taken an active role in a troubling case involving a missing minor Ladakhi girl from a tribal Buddhist community. Found in Srinagar with a Muslim boy, the girl went missing late December, raising serious concerns about human rights violations.
Currently under the care of a Child Welfare Committee, the young girl is reported to be experiencing mental trauma. Complainant Sagar Bhante from Bhopal has urged the commission for an impartial investigation and justice for the girl amidst local social pressures that allegedly undermine the case's seriousness.
With a focus on justice and accountability, the NHRC has directed Leh's civil and police authorities to investigate the case truthfully and submit a detailed report. The commission's intervention underscores the importance of safeguarding the victim's rights and well-being.
(With inputs from agencies.)

Source: https://www.hindustantimes.com/india-news/minor-ladakhi-girl-case-nhrc-notice-to-leh-dc-police-authorities-101767447743865-amp.html

Minor Ladakhi girl case: NHRC notice to Leh DC, police authorities

Published on: Jan 03, 2026 7:12 PM IST

PTI

New Delhi, The NHRC has issued a notice to the Leh civil administration and its police authorities over charges that a minor Ladakhi girl belonging to a tribal Buddhist community who had gone missing from her home late December, was subsequently "found in Srinagar with a Muslim boy," according to the proceedings of the case.

Minor Ladakhi girl case: NHRC notice to Leh DC, police authorities

Presently, the girl is under the supervision of a Child Welfare Committee and is suffering from "mental trauma," the proceedings dated January 2 said.

The complainant is Sagar Bhante, from Bhopal in Madhya Pradesh, it said.

"The complainant alleged that on December 26, a minor Khalatse Ladakhi girl belonging to a tribal Buddhist community went missing from her home. The complainant further alleged that her family immediately lodged a missing complaint with the PS Khalatse, FIR No.39/2025 dated 28.12.2025, u/s 137 BNS and under the POCSO Act. During the police investigation, the said girl was found in Srinagar with a Muslim boy," it said.

"Presently, the girl is under the supervision of CWC, and she is now in mental trauma," the proceedings said.

The complainant had sought the intervention of the commission and requested an "impartial investigation into the role of other individuals involved in the crime, justice for the victim girl and her family, protection, counselling with medical, psychological, and legal assistance.

"Due to social pressure at the local level, this sensitive case is not receiving the seriousness it warrants. A detailed action-taken report should be sought from the police and the administration, in accordance with the law," it said.

The allegations made in the complaint prima facie seem to be violations of the human rights of the victim, the rights panel said.

A bench of the National Human Rights Commission , presided by its member Priyank Kanoongo, has taken cognisance under section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

"The Registry is directed to issue a notice to the DC , Leh and the SSP/DIG, Leh, Ladakh, with directions to get the allegations made in the complaint inquired into and to submit an action taken report within seven days for perusal of the Commission," it adds.

This article was generated from an automated news agency feed without modifications to text.

Source: https://indianmasterminds.com/news/ips-mukesh-singh-appointed-dgp-ladakh-174028/

Who Is IPS Mukesh Singh? Senior AGMUT Cadre Officer Appointed DGP of Ladakh, Replaces Shiv Darshan Singh Jamwal

Originally belonging to the Jammu and Kashmir cadre, Singh continued under the AGMUT cadre following its reorganization in 2019.

January 3, 2026

Indian Masterminds Bureau

New Delhi/Ladakh: In a significant administrative reshuffle within the Indian Police Service (IPS), the Ministry of Home Affairs (MHA) on Friday effected a series of high-level postings involving senior IPS officers from the AGMUT cadre (Arunachal Pradesh–Goa–Mizoram–Union Territories). The changes include the appointment of Mukesh Singh (IPS: 1996: AGMUT) as the new Director General of Police (DGP), Ladakh, along with transfers and new postings in Arunachal Pradesh and Delhi.

Mukesh Singh Takes Charge as DGP, Ladakh

Senior IPS officer Mukesh Singh, a 1996-batch AGMUT cadre officer, has been appointed as the Director General of Police of Ladakh following his repatriation from central deputation. He replaces Shiv Darshan Singh Jamwal (IPS: 1995: AGMUT), who has been transferred and appointed as the new DGP of Arunachal Pradesh.

The MHA formally issued the posting order on Friday, marking Singh's return to a key

Leadership Transition in Arunachal Pradesh Police

Alongside Singh's appointment, the MHA also announced major changes in Arunachal Pradesh:

Anand Mohan (IPS: 1994: AGMUT), who was serving as the DGP of Arunachal Pradesh, has been transferred to Delhi.

Shiv Darshan Singh Jamwal (IPS: 1995: AGMUT) has been appointed as the new DGP of Arunachal Pradesh, replacing Anand Mohan.

Jamwal was serving as DGP, Ladakh prior to this reassignment.

Profile: Mukesh Singh – Veteran Counter-Terrorism Specialist

Early Life and Education

Date of Birth: January 24, 1971

Place of Birth: Bokaro Steel City, Bihar (now in Jharkhand)

Education:

B.Tech in Civil Engineering, Indian Institute of Technology (IIT), Delhi

Police Training: Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (SVPNPA), 1996 batch

Career Overview and Policing Experience

Mukesh Singh is widely regarded as one of India's most experienced counter-terrorism and internal security specialists.

Jammu and Kashmir Policing

Originally belonging to the Jammu and Kashmir cadre, Singh continued under the AGMUT cadre following its reorganization in 2019. His field experience includes some of the most militancy-affected regions in the country:

Senior Superintendent of Police (SSP): Jammu, Reasi, Pulwama, and Poonch

Inspector General of Police (IGP): Jammu Range

Additional Director General of Police (ADGP): Jammu Zone

These assignments were carried out during periods of intense militancy and security challenges.

Key Role in National Investigation Agency (NIA)

Mukesh Singh was a founding member of the core team that established the National Investigation Agency (NIA). During his tenure, he served in multiple leadership roles:

Superintendent of Police (SP)

Deputy Inspector General (DIG)

Inspector General (IG)

At the NIA, Singh investigated several high-profile terror and national security cases, gaining recognition for his operational and investigative expertise.

Central Deputation with ITBP

Before his appointment as DGP, Ladakh, Singh served on central deputation with the Indo-Tibetan Border Police (ITBP):

Inspector General (IG), ITBP: From 2023

Additional Director General (ADG), ITBP: From September 2025 until January 2026

His experience with ITBP further strengthened his exposure to border security and high-altitude operations, making him well-suited for the Ladakh posting.

Other Key Assignments

In addition to his major postings, Singh has also served in:

Delhi Police

National Human Rights Commission (NHRC) as SSP

IGP (Crime), Jammu & Kashmir

IGP (Personnel), Police Headquarters, J&K

Awards and Decorations

Mukesh Singh’s service record is marked by several prestigious gallantry and service awards:

Police Medal for Gallantry (PMG):

First award in 2003

Bar (second award) in 2005

Sher-e-Kashmir Police Medal for Gallantry: 2002

President’s Police Medal for Distinguished Service: 2014

DGP’s Commendation Medal: 1999

Army Commander Commendation Medal: 2005

Contributions to Policing Literature

Apart from operational policing, Singh has made notable contributions to academic and professional literature on security and law enforcement. His works include:

Books

Police Operations

Curse of the Pir

Research Papers

Conducting an Anti-Terrorist Operation (2014)

Police Operations (2015)

Investigation of Encounter Killings (2016)

Strategic Importance of Ladakh Posting

Ladakh, given its geopolitical sensitivity, border dynamics, and internal security challenges, requires experienced leadership. Mukesh Singh’s background in counter-terrorism, border policing, and central armed forces positions him as a critical choice for maintaining law and order in the Union Territory.

Operational Priorities

With this reshuffle, the Ministry of Home Affairs has placed seasoned officers in key strategic roles. Mukesh Singh’s appointment as DGP, Ladakh, Anand Mohan’s transfer to Delhi, and Shiv Darshan Singh Jamwal’s elevation as DGP, Arunachal Pradesh, reflect a broader effort to align experience with operational priorities across sensitive regions of the country.

Source: https://kashmirvision.in/2026/01/03/minor-ladakhi-girl-case-nhrc-notice-to-leh-dc-police-authorities/

Minor Ladakhi girl case: NHRC notice to Leh DC, police authorities

Added on January 3, 2026 KV Network

NEW DELHI, Jan 3 (PTI): The NHRC has issued a notice to the Leh civil administration and its police authorities over charges that a minor Ladakhi girl belonging to a tribal Buddhist community who had gone missing from her home late December, was subsequently “found in Srinagar with a Muslim boy,” according to the proceedings of the case.

Presently, the girl is under the supervision of a Child Welfare Committee (CWC) and is suffering from “mental trauma,” the proceedings dated January 2 said.

The complainant is Sagar Bhante, from Bhopal in Madhya Pradesh, it said.

Source: https://newsarenaindia.com/states/nhrc-notice-to-leh-dc-police-in-minor-ladakhi-girl-s-case/66447

NHRC notice to Leh DC, Police in minor Ladakhi girl's case

The complainant alleged that on December 26, a minor Khalatse Ladakhi girl belonging to a tribal Buddhist community went missing from her home.She was subsequently “found in Srinagar with a Muslim boy,” according to the proceedings of the case.

News Arena Network - New Delhi - UPDATED: January 3, 2026, 08:18 PM - 2 min read

Noting that the allegations made in the case reflect violations of huan rights, the NHRC has issued a notice to the Leh civil administration and its police authorities over charges that a minor Ladakhi girl belonging to a tribal Buddhist community who had gone missing from her home late December. She was subsequently “found in Srinagar with a Muslim boy,” according to the proceedings of the case.

A bench of the National Human Rights Commission , presided by its member Priyank Kanoongo, has taken cognisance under section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993. The allegations made in the complaint prima facie seem to be violations of the human rights of the victim, the rights panel said.

“The Registry is directed to issue a notice to the DC , Leh and the SSP/DIG, Leh, Ladakh, with directions to get the allegations made in the complaint inquired into and to submit an action taken report within seven days for perusal of the Commission,” it adds.

Presently, the girl is under the supervision of a Child Welfare Committee (CWC) and is suffering from “mental trauma,” the proceedings dated January 2 said.The complainant is Sagar Bhante, from Bhopal in Madhya Pradesh, it said.

“The complainant alleged that on December 26, a minor Khalatse Ladakhi girl belonging to a tribal Buddhist community went missing from her home. The complainant further alleged that her family immediately lodged a missing complaint with the PS Khalatse, FIR No.39/2025 dated 28.12.2025, u/s 137 BNS and under the POCSO Act. During the police investigation, the said girl was found in Srinagar with a Muslim boy,” it said.

“Presently, the girl is under the supervision of CWC, and she is now in mental trauma,” the proceedings said.The complainant had sought the intervention of the commission and requested an “impartial investigation into the role of other individuals involved in the crime, justice for the victim girl and her family, protection, counselling with medical, psychological, and legal assistance.“Due to social pressure at the local level, this sensitive case is not receiving the seriousness it warrants. A detailed action-taken report should be sought from the police and the administration, in accordance with the law,” it said.

Source: https://www.opindia.com/news-updates/ladakh-nhrc-writes-to-police-after-muslim-accused-abducts-minor-buddhist-girl-case-registered-under-pocso/

Ladakh: NHRC writes to police after Muslim accused abducts minor Buddhist girl, case registered under POCSO

Written by Dibakar Dutta
Last modified at 6:49 PM, January 3, 2026
January 3, 2026 | 6:47 PM

On Friday (2nd January), the National Human Rights Commission (NHRC) has written to the Senior Superintendent of Police (SSP) and the Deputy Commissioner of Police in Ladakh in connection with the abduction of a minor Buddhist girl.

According to the statutory body, a minor tribal girl belonging to the Buddhist community was abducted on 26th December last year by a Muslim man. Two days later, a First Information Report (FIR) was lodged in connection with the case on 28th December.

The case was registered under Section 137(2) of Bharatiya Nyay Sanhita (BNS) and relevant sections of the POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) Act.

Following the initial investigation, the police recovered the minor Buddhist girl from Srinagar. She was found in a state of mental trauma and is currently under the supervision of the Child Welfare Committee (CWC).

NHRC pointed out that the sensitive case is not receiving the seriousness it warrants from the Ladakh administration and sought a detailed action-taken report from the police and the local administration within 7 days.

“The allegations made in the complaint prima facie seem to be violations of the human rights of the victim,” the letter stated.

“The Bench of the National Human Rights Commission, presided by Shri Priyank Kanoongo, Hon’ble Member, has taken cognizance u/s 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, in the matter,” it emphasised.

Source: https://thelogicalindian.com/indores-water-crisis-claims-ten-lives-after-sewage-leakage-contaminates-drinking-supply-in-bhagirathpura/

Indore's Water Crisis Claims Ten Lives After Sewage Leakage Contaminates Drinking Supply In Bhagirathpura

Indore Water Contamination: Ten lives were lost and 1,400 residents fell ill after sewage contaminated drinking water in Indore.

Aanchal Mishra | January 3, 2026

The Bhagirathpura area of Indore, Madhya Pradesh, faced a grim milestone as the death toll from a massive diarrhoea outbreak reached at least 10, the times of India reported.

More than 1,400 residents have been affected by contaminated drinking water, with over 200 people currently admitted across 27 hospitals. Laboratory tests conducted by a city-based medical college confirmed that the water supply was breached by sewage bacteria due to a leak in the main pipeline near a police outpost.

Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has termed the incident a "tragic failure" and ordered the immediate removal of several senior municipal officials, including the Additional Commissioner, as the National Human Rights Commission steps in to investigate.

Infrastructure Failure

Indore, consistently ranked as India's cleanest city, is now grappling with a public health catastrophe that exposes a dark side of rapid urban development. The crisis began in late December 2025, when residents of Bhagirathpura started reporting symptoms of high fever, vomiting, and severe diarrhoea.

Local families had repeatedly complained to the Indore Municipal Corporation about foul-smelling, murky water for days, yet their warnings were ignored until the casualties began to mount.

The contamination was eventually traced back to a specific leakage point in a major supply line located beneath a recently constructed toilet at a police check post, allowing raw sewage to seep directly into the drinking water.

A Growing Toll

While official health department data initially verified four deaths, Indore Mayor Pushyamitra Bhargava admitted that information regarding at least 10 fatalities has been received. Among the victims was a six-month-old infant who fell ill on December 26 and succumbed to high fever and dehydration by December 29.

Chief Medical and Health Officer Dr Madhav Prasad Hasani stated that while the report confirms bacterial presence, work is ongoing to identify the specific strain.

In a stern administrative crackdown, Chief Minister Mohan Yadav has relieved the In-Charge Superintending Engineer of the Water Distribution Department and issued charge sheets to several others, stating that "corrective measures" will be reviewed across all 16 municipal corporations in the state.

Community In Fear

Despite municipal assurances and the deployment of water tankers, a deep-seated distrust remains among the residents of Bhagirathpura. Many families are now forced to buy bottled water for drinking, fearing that even the government-supplied tankers might be compromised.

"We no longer have trust in this system; this is destruction carried out in the name of development," a local resident whose 15-year-old daughter is currently hospitalised told media outlets.

While Urban Development Minister Kailash Vijayvargiya has promised that "micro-checking" of the entire colony will be completed within 10 days, the delay in repairing the aging pipelines, reportedly stalled for months despite earlier tenders, highlights a systemic failure in prioritising citizen safety over administrative bureaucracy.

The Logical Indian's Perspective

At The Logical Indian, we believe that the title of "Cleanest City" becomes a hollow accolade when its citizens are

forced to die from preventable water-borne diseases. Access to safe drinking water is not a luxury; it is a fundamental human right that must be safeguarded with more than just awards and optics.

This tragedy is a result of criminal negligence, where sewage-water intersections were allowed to persist despite clear warnings from the community.

We advocate for a complete, transparent audit of water infrastructure across all urban hubs and the implementation of real-time water quality monitoring. True development is measured by the health of the most vulnerable, not just the cleanliness of the streets.

News in Q&A

1. How did sewage enter the drinking water of India’s cleanest city? The contamination occurred due to a “criminal” design flaw where a main drinking water pipeline passed directly beneath a public toilet at a police outpost. A leak in the aging line allowed raw sewage from the toilet’s pit to mix with the water supply.

2. What is the actual death toll and the scale of the outbreak? While the health department officially records 4 deaths, Mayor Pushyamitra Bhargava and local residents have confirmed 10 fatalities. Over 1,400 people have been treated for vomiting and diarrhoea, with 32 patients still in critical condition in ICUs.

3. Why did the municipal authorities fail to prevent this? Negligence is the primary allegation. Residents had complained about dirty water for days, but no action was taken. Furthermore, a tender for a new pipeline had been pending since August 2025, but work remained stalled due to administrative apathy.

4. What action has been taken against the responsible officials? CM Mohan Yadav has removed Indore Municipal Commissioner Dilip Kumar Yadav and suspended Additional Commissioner Rohit Sisonia and In-charge Superintending Engineer Sanjeev Shrivastava. Show-cause notices have been issued to the entire top brass of the IMC.

5. Is the water in Indore safe to drink now? Authorities have replaced the contaminated water in the lines and repaired the leaks. However, a “boil water” advisory remains in effect for all Bhagirathpura residents as a precaution until further culture reports confirm the water is completely sterile.

Source: https://www.tribuneindia.com/news/j-k/nhrc-notice-to-leh-dc-police-authorities-over-minor-ladakhi-girl-case/amp

Tribune India

NHRC notice to Leh DC, police authorities over minor Ladakhi girl case

Had gone missing from her home in December and subsequently 'found in Srinagar with a Muslim boy'

PTI | New Delhi, Updated At : 03:45 AM Jan 04, 2026 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Leh civil administration and its police authorities over charges that a minor Ladakhi girl belonging to a tribal Buddhist community who had gone missing from her home late December, was subsequently “found in Srinagar with a Muslim boy,” according to the proceedings of the case.

Presently, the girl is under the supervision of a Child Welfare Committee (CWC) and is suffering from “mental trauma,” the proceedings dated January 2 said.

The complainant is Sagar Bhante, from Bhopal in Madhya Pradesh, it said.

“The complainant alleged that on December 26, a minor Khalatse Ladakhi girl belonging to a tribal Buddhist community went missing from her home. The complainant further alleged that her family immediately lodged a missing complaint with the PS Khalatse, FIR No.39/2025 dated 28.12.2025, u/s 137(2) BNS and under the POCSO Act. During the police investigation, the said girl was found in Srinagar with a Muslim boy,” it said.

“Presently, the girl is under the supervision of CWC, and she is now in mental trauma,” the proceedings said.

The complainant had sought the intervention of the commission and requested an “impartial investigation into the role of other individuals involved in the crime, justice for the victim girl and her family, protection, counselling with medical, psychological, and legal assistance.

“Due to social pressure at the local level, this sensitive case is not receiving the seriousness it warrants. A detailed action-taken report should be sought from the police and the administration, in accordance with the law,” it said.

The allegations made in the complaint prima facie seem to be violations of the human rights of the victim, the rights panel said.

A bench of the National Human Rights Commission (NHRC), presided by its member Priyank Kanoongo, has taken cognisance under section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

“The Registry is directed to issue a notice to the DC (Deputy Commissioner), Leh and the SSP/DIG, Leh, Ladakh, with directions to get the allegations made in the complaint inquired into and to submit an action taken report within seven days for perusal of the Commission,” it adds.

Source: https://bhilwarahalchal.com/rajasthan/in-jalore-a-panchayat-has-banned-women-from-using-smartphones-the-nhrc-has-issued-a-notice-to-the-district-magistrate-for-an-inquiry-667517

जालौर में महिलाओं के स्मार्टफोन पर पंचायत पाबंदी, एनएचआरसी ने जिलाधिकारी को जांच का नोटिस जारी

By - राजकुमार माली | 4 Jan 2026 7:20 AM

जालौर जिले के 15 गांवों की महिलाओं के कैमरे वाले स्मार्टफोन उपयोग पर पाबंदी के पंचायत आदेश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है। आयोग को इस संबंध में शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए जालौर के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया गया है।आयोग ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करें और दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को दें।यह विवाद जालौर जिले के गाजीपुर गांव में हुई चौधरी समाज की सुंधामाता पट्टी की पंचायत के फैसले को लेकर है। पंचायत ने 15 गांवों की महिलाओं के लिए कैमरे वाले स्मार्टफोन के उपयोग पर पाबंदी लगाई है। यह पाबंदी 26 जनवरी से लागू होगी।पंचायत के निर्णय के अनुसार, महिलाएं अब केवल की-पैड वाले फोन का उपयोग कर सकेंगी। इसके अलावा महिलाओं को शादी समारोह, सामाजिक कार्यक्रम या पड़ोसी के घर जाने के दौरान मोबाइल फोन ले जाने से भी रोका गया है।एनएचआरसी में इस शिकायत पर आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार कानून 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया। आयोग ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों से प्रतीत होता है कि यह पाबंदी विशेष रूप से महिलाओं पर लागू की गई है, जो कि लिंग आधारित और गलत है।शिकायत में यह भी कहा गया कि पंचायत या सामाजिक समूह के पास यह तय करने का अधिकार नहीं है कि महिलाएं किस तरह फोन या तकनीक का उपयोग करें। आयोग ने स्पष्ट किया कि यह आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इसके लिए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे जांच कर दो सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और भविष्य में किसी प्रकार की पाबंदी या भेदभाव रोका जा सके।

Dainik Bhaskar, Online News, 04/01/2026

Source: https://www.bhaskar.com/local/jharkhand/chaibasa/news/human-rights-commission-seeks-report-on-chaibasa-lathi-charge-case-136851462.html

चाईबासा में लाठी चार्ज मामले में मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट

चाईबासा4 घंटे पहले

चाईबासा| राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के सहायक रजिस्ट्रार अतुल कुमार ने पश्चिम सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक से चाईबासा में हुए आदिवासियों पर लाठी चार्ज की विस्तृत रिपोर्ट 28 दिनों के भीतर मांग की है। पुलिस अधीक्षक को ईमेल के जरिए भेजे गए पत्र में सहायक रजिस्ट्रार अतुल कुमार ने कहा है कि समाजसेवी व आरटीआई एक्टिविस्ट सिर्मा देवगम द्वारा मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में दर्ज कराई गई। शिकायत के आलोक में 28 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। जानकारी हो कि आरटीआई एक्टिविस्ट व समाजसेवी सिर्मा देवगम ने मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के समक्ष एक केस दर्ज कराया है। मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली को लिखे पत्र में श्री देवगम ने कहा है कि पश्चिम सिंहभूम के एनएच-220 व बाईपास सड़क पर नो एंट्री की मांग को लेकर गत 28 अक्टूबर 25 को चाईबासा के ताम्बो चौक पर ग्रामीणों द्वारा शांति पूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। रात को लगभग 11 बजे पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे जिस वजह से धरने में शामिल बच्चे, बूढ़े व महिलाओं सहित सैकड़ों ग्रामीण घायल हुए।

चाईबासा| नए साल के अवसर पर सहायक पुलिस संघ का एक प्रतिनिधिमंडल शनिवार को नए उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने उप विकास आयुक्त को गुलदस्ता भेंट किया। इस दौरान संघ ने डीडीसी के नेतृत्व में जिला विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और जनहित से जुड़ी योजनाएं और अधिक प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारे जाने की बात कही। इस मौके पर संघ के अध्यक्ष उमेश मुंडारी, गोनो तैसुम, चांदमुनी जमुदा, प्रीति बारहा, सुलोचना पूर्ति, श्याम सुंदर महतो समेत अन्य लोग शामिल थे।

Dainik Bhaskar, Online News, 04/01/2026

Source: https://www.bhaskar.com/amp/local/uttar-pradesh/sambhal/pawasa/news/wanted-accused-arrested-in-sambhal-fraud-case-136847809.html

संभल में धोखाधड़ी मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:न्यायालय के वारंट पर हयातनगर पुलिस ने की कार्रवाई

भूपेंद्र सिंह | पंवासा(पंवासा), संभल 5 घंटे पहले

संभल की हयातनगर पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ न्यायालय से वारंट जारी था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।

पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार बिश्नोई के निर्देश पर जनपद में अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह गिरफ्तारी हुई। अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) और क्षेत्राधिकारी संभल के पर्यवेक्षण में हयातनगर पुलिस ने यह कार्रवाई की।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान थाना हयातनगर क्षेत्र के ग्राम आढौल निवासी कामिल पुत्र भूरा (उम्र करीब 30 वर्ष) के रूप में हुई है। उसके खिलाफ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, संभल में एक परिवाद दाखिल था।

न्यायालय द्वारा जारी वारंट के आधार पर कामिल को पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया।

आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूरी करने के बाद अभियुक्त को माननीय न्यायालय में पेशी के लिए भेज दिया गया। गिरफ्तारी टीम में उप निरीक्षक रामखिलावन और कॉन्स्टेबल मोहन कुमार शामिल थे। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूती मिली है।

Source: https://www.drishtiias.com/hindi/state-pcs-current-affairs/contaminated-water-deaths-in-indore

इंदौर में दूषित जल से मृत्यु

03 Jan 2026
15 min read

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पेयजल के सेवन से सात लोगों की मृत्यु तथा 40 से अधिक व्यक्तियों के अस्पताल में भर्ती होने की गंभीर घटना का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने स्वतः संज्ञान लिया।

मुख्य बिंदु

संदूषण का कारण: पीने के पानी की मुख्य पाइपलाइन एक सार्वजनिक शौचालय के नीचे से होकर गुजरती है, जिसमें रिसाव होने के कारण सीवेज जल पेयजल में मिल गया।

इसके अतिरिक्त, पानी की कई वितरण लाइनें क्षतिग्रस्त पाई गईं, जिसके परिणामस्वरूप दूषित जल सीधे घरों तक पहुँच गया।

NHRC की कार्रवाई: इस घटना को मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के रूप में देखते हुए, NHRC ने मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है।

आयोग ने मुख्य सचिव को दो सप्ताह के भीतर एक विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

अवलोकन: आयोग ने स्पष्ट किया कि निवासियों द्वारा कई दिनों तक दूषित जल की शिकायतों के बावजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी और समयोचित कार्रवाई नहीं की गई, जो जीवन के अधिकार तथा स्वास्थ्य के अधिकार का घोर उल्लंघन है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

परिचय:

भारत का NHRC मानव अधिकारों को बढ़ावा और संरक्षण देने के लिये स्थापित एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है।

स्थापना:

इसका गठन 12 अक्तूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 के तहत किया गया था, जिसे बाद में वर्ष 2006 और वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था।

आयोग की स्थापना पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप की गई थी, जो मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षण के लिये अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं।

पेरिस सिद्धांत मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण के लिये पेरिस (अक्तूबर, 1991) में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का समूह है तथा 20 दिसंबर, 1993 को संयुक्त राष्ट्र (UN) की महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था।

ये सिद्धांत विश्व भर में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं (NHRI) के कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं।

Source: https://www.ibc24.in/country/nhrc-issues-notice-to-leh-deputy-commissioner-police-officials-in-case-of-minor-ladakhi-girl-3410485.html

नाबालिग लद्दाखी लड़की के मामले में एनएचआरसी का लेह के उपायुक्त, पुलिस अधिकारियों को नोटिस

Bhasha
Modified Date: January 3, 2026 / 08:09 pm IST
Published Date: January 3, 2026 8:09 pm IST

नयी दिल्ली, तीन जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इन आरोपों को लेकर लेह प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को एक नोटिस जारी किया है कि दिसंबर के अंत में अपने घर से लापता हुई बौद्ध समुदाय की एक नाबालिग आदिवासी लड़की बाद में "श्रीनगर में एक मुस्लिम लड़के के साथ मिली।"

दो जनवरी की मामले की कार्यवाही में कहा गया है कि लड़की फिलहाल बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की देखरेख में है और "मानसिक आघात" का सामना कर रही है।

मध्य प्रदेश के भोपाल के निवासी शिकायतकर्ता सागर भंते के अनुसार, शिकायत में कहा गया है कि 26 दिसंबर को आदिवासी बौद्ध समुदाय से संबंध रखने वाली एक नाबालिग लद्दाखी लड़की अपने घर से लापता हो गई थी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके परिवार ने तुरंत खलत्से थाने में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के दौरान, उक्त लड़की श्रीनगर में एक मुस्लिम लड़के के साथ पाई गई।

कार्यवाही में कहा गया है, "फिलहाल, लड़की बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की देखरेख में है, और वह मानसिक आघात का सामना कर रही है।"

शिकायतकर्ता ने आयोग से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और "अपराध में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच, पीड़िता लड़की और उसके परिवार के लिए न्याय, सुरक्षा, काउंसलिंग, चिकित्सा, मानसिक और कानूनी सहायता की मांग की।"

शिकायत में कहा गया है, "स्थानीय स्तर पर सामाजिक दबाव के कारण इस संवेदनशील मामले पर गंभीरता से चर्चा नहीं हुई। पुलिस और प्रशासन से कानून के अनुसार एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट ली जानी चाहिए।"

मानवाधिकार आयोग ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के अनुसार, प्रारंभिक रूप से पीड़िता के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है।

आयोग ने 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया है।

आयोग ने कहा, "रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वह लेह के उपायुक्त (डीसी) और लेह, लद्दाख के एसएसपी/डीआईजी को नोटिस जारी करें और शिकायत में लगाये गये आरोपों की जांच कराएं। सात दिन में आयोग के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।"

भाषा जोहेब सुरेश
सुरेश

Source: https://www.jagran.com/news/national-nhrc-sent-notice-to-jalore-dm-regarding-ban-on-women-using-smartphones-in-15-villages-40095000.html

'महिलाएं नहीं कर सकतीं स्मार्टफोन का इस्तेमाल', राजस्थान के 15 गांवों में लगी पाबंदी पर NHRC का एक्शन; भेजा नोटिस

By Jagran News Edited By: Abhishek Pratap Singh
Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:10 PM (IST)

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान के जालौर जिले के 15 गांवों में महिलाओं द्वारा कैमरे वाले स्मार्टफोन के उपयोग पर पंचायत द्वारा लगाई गई पाबंदी का संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संबंध में मिली शिकायत पर जालौर के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। राजस्थान के जालौर जिले के 15 गांवों की महिलाओं के कैमरे वाला स्मार्टफोन उपयोग करने पर पाबंदी के पंचायत के आदेश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संबंध में मिली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जालौर के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है।

जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करके दो सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को दें। राजस्थान के जालौर जिले की गाजीपुर गांव में हुई चौधरी समाज की सुंधामाता पट्टी की पंचायत ने 15 गांवों की महिलाओं के लिए कैमरे वाले स्मार्टफोन के उपयोग पर पाबंदी लगाई है। पाबंदी का यह नियम 26 जनवरी से लागू होना है।

महिलाओं पर लगाई गईं कई पाबंदियां

पंचायत के फैसले के मुताबिक महिलाएं अब स्मार्टफोन की जगह की-पैड फोन का ही उपयोग कर सकेंगी। इतना ही नहीं महिलाओं के शादी समारोह आदि सामाजिक कार्यक्रमों और पड़ोसी के घर जाते समय भी मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। इस संबंध में राष्ट्रीय मानावाधिकार आयोग को शिकायत मिली है।

इस शिकायत पर आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार कानून 1993 की धारा 12 के तहत संज्ञान लिया और जालौर जिले के जिलाधिकारी को नोटिस जारी किया है।

जिलाधिकारी ने दिए निर्देश

आयोग ने जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि वह शिकायत की जांच करके दो सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट आयोग को दें। आयोग को मिली शिकायत में कहा गया है कि स्मार्टफोन पर प्रतिबंध विशेषरूप से महिलाओं पर लगाया गया है जो कि लिंग आधारित प्रतिबंध है और ये गलत है।

शिकायत में क्या कहा गया?

शिकायत में कहा गया है कि पंचायत या सामाजिक समूह को यह तय करने का अधिकार नहीं है कि महिलाएं किस तरह फोन का उपयोग करेंगी या तकनीक का इस्तेमाल करेंगी।

शिकायत में आयोग से मामले में दखल देने का आग्रह करते हुए अनुरोध किया गया है कि कुछ उपाय किए जाएं ताकि आगे चल कर लड़कियों पर शिक्षा या आने-जाने आदि पर पाबंदी न लगा दी जाए। आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया पीड़ितों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं।

Source: https://hindi.moneycontrol.com/india/9-people-died-from-sewer-water-bacteria-shocking-revelation-in-indore-case-article-2327834.html

Indore Water Tragedy: सीवर वॉटर बैक्टीरिया से हुई 9 लोगों की मौत! इंदौर मामले में चौंकाने वाला खुलासा

Indore Water Tragedy: इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में कम से कम नौ लोगों की मौत की जांच के शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि पीने के पानी के नमूनों में ऐसी बैक्टीरिया मिली है, जो आमतौर पर नालियों के पानी में पाई जाती है। अधिकारियों ने यह जानकारी गुरुवार को दी।
Translated By: Ashwani Kumar Srivastava
अपडेटेड Jan 02, 2026 पर 9:47 AM
Indore Water Tragedy: इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में कम से कम नौ लोगों की मौत की जांच के शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया है कि पीने के पानी के नमूनों में ऐसी बैक्टीरिया मिली है, जो आमतौर पर नालियों के पानी में पाई जाती है। अधिकारियों ने यह जानकारी गुरुवार को दी। बता दें कि यह घटना उस समय हुई जब पहले मृतकों को उल्टी और दस्त की शिकायत के साथ अस्पताल लाया गया था।
अधिकारियों ने पहले कहा था कि सीवेज पाइपलाइन से पीने के पानी की पाइपलाइन में रिसाव होने के कारण ही बैक्टीरिया संक्रमण फैला है। गुरुवार को उन्होंने आगे कहा कि विशिष्ट रोगजनक (pathogens) की पहचान के लिए और अधिक परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है। बुधवार को मृतकों की पुष्टि चार हुई थी, जो अब बढ़कर कुल संख्या में हो गई है। इलाके के कम से कम 150 और निवासियों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
इस बीच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को इन मौतों के संबंध में नोटिस जारी किया है।
इंदौर स्थित महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घंघोरिया ने कहा, "प्रारंभिक रिपोर्ट में मानव मल युक्त सीवर के पानी में पाए जाने वाले असामान्य बैक्टीरिया की उपस्थिति की पुष्टि हुई है। हालांकि, बैक्टीरिया की पहचान अभी बाकी है, क्योंकि बैक्टीरिया की कल्चर रिपोर्ट का इंतजार है। प्रभावित मरीजों के मल परीक्षण की रिपोर्ट भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है - उससे भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।"
स्थानीय प्रशासन के अनुसार, निवासियों ने सबसे पहले 25 दिसंबर को पानी में अजीब गंध की शिकायत की थी। एक निवासी ने बताया, "समस्याएं पिछले कुछ हफ्तों से चल रही थीं, लेकिन 25 दिसंबर को और बढ़ गईं।"
जांच समिति के प्रमुख और अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने बताया, "कुल मिलाकर इस क्षेत्र में 14 मौतें हुई हैं। जांच समिति ने पाया कि इनमें से 9 मौतें दस्त के कारण हुईं। अन्य मौतें सह-बीमारी और एक दुर्घटना के कारण हुईं। 21 दिसंबर को एक महिला की मौत हुई थी, लेकिन उसे भी गलत तरीके से पानी के दूषित होने से जोड़ दिया गया।"
स्वास्थ्य अधिकारी ने दी जानकारी
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. माधव हसनी ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग को महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला में जांचे गए पानी के नमूनों की रिपोर्ट मिली है। उन्होंने आगे कहा, "रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि हानिकारक बैक्टीरिया युक्त दूषित पानी पीने से लोग बीमार पड़े और उनकी मौत हुई। पाइपलाइन में रिसाव के कारण पानी दूषित हुआ था।"
इस बीच, मामले से परिचित अधिकारियों ने बताया कि भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण बीमार पड़ने वालों की संख्या बढ़ रही है। 2,456 लोग उल्टी और दस्त के लक्षणों से ग्रसित हैं, जिनमें से 162 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कुलकर्णी भट्टा क्षेत्र के 40 वर्षीय अरविंद लिखार की गुरुवार को मृत्यु हो गई। उनकी बेटी महक ने बताया, "वह भागीरथपुरा क्षेत्र में मजदूर के रूप में काम करते थे और रविवार को वहां का पानी पीने के बाद बीमार पड़ गए।"
अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय दुबे ने उस क्षेत्र का निरीक्षण किया जहां दूषित पानी के आपूर्ति लाइन में प्रवेश करने का संदेह है और नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा, "ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। शहर के अन्य हिस्सों में भी पीने के पानी के रैंडम सैंपलिंग की जानी चाहिए। पेयजल से संबंधित मामलों को लंबित नहीं रखा जाना चाहिए और जनहित को ध्यान में रखते हुए मंजूरी तुरंत दी जाने चाहिए।"
अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बारे में उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा कर्तव्य पालन में हुई चूक की जांच चल रही है, क्योंकि 30 साल पुरानी पाइपलाइनों में रिसाव की जांच करना मुश्किल था।
कैलाश विजयवर्गीय ने अपने आपत्तिजनक बयान पर जताया खेद
इससे पहले दिन में, मध्य प्रदेश के शहरी विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में फैले डायरिया के प्रकोप के संबंध में मीडिया से बातचीत के दौरान एक आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग करके विवाद खड़ा कर दिया। वायरल वीडियो के बाद हुई आलोचना के बाद, विजयवर्गीय ने खेद व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया।
उन्होंने कहा, "मेरी टीम और मैं पिछले दो दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ ने अपनी जान गंवाई है। गहरे दुख की इस स्थिति में, मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गए। मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं।"

विजयवर्गीय ने गुरुवार को चार पीड़ितों के परिवारों को 2 लाख रुपये के चेक सौंपे। उन्होंने कहा, “स्वास्थ्य विभाग से पुष्टि मिलने के बाद हम सभी पीड़ितों को मुआवजा देंगे।”

NHRC ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए पाया कि यह घटना पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। मानवाधिकार आयोग ने बताया कि इसके मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

Source: https://hindi.theprint.in/india/nhrc-issues-notice-to-leh-deputy-commissioner-police-officials-in-case-of-minor-ladakhi-girl/914802/

नाबालिग लद्दाखी लड़की के मामले में एनएचआरसी का लेह के उपायुक्त, पुलिस अधिकारियों को नोटिस

भाषा | 3 January, 2026

नयी दिल्ली, तीन जनवरी (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने इन आरोपों को लेकर लेह प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को एक नोटिस जारी किया है कि दिसंबर के अंत में अपने घर से लापता हुई बौद्ध समुदाय की एक नाबालिग आदिवासी लड़की बाद में "श्रीनगर में एक मुस्लिम लड़के के साथ मिली।"

दो जनवरी की मामले की कार्यवाही में कहा गया है कि लड़की फिलहाल बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की देखरेख में है और "मानसिक आघात" का सामना कर रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल के निवासी शिकायतकर्ता सागर भंते के अनुसार, शिकायत में कहा गया है कि 26 दिसंबर को आदिवासी बौद्ध समुदाय से संबंध रखने वाली एक नाबालिग लद्दाखी लड़की अपने घर से लापता हो गई थी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके परिवार ने तुरंत खलत्से थाने में लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस जांच के दौरान, उक्त लड़की श्रीनगर में एक मुस्लिम लड़के के साथ पाई गई।

कार्यवाही में कहा गया है, "फिलहाल, लड़की बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) की देखरेख में है, और वह मानसिक आघात का सामना कर रही है।"

शिकायतकर्ता ने आयोग से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया और "अपराध में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच, पीड़िता लड़की और उसके परिवार के लिए न्याय, सुरक्षा, काउंसलिंग, चिकित्सा, मानसिक और कानूनी सहायता की मांग की।"

शिकायत में कहा गया है, "स्थानीय स्तर पर सामाजिक दबाव के कारण इस संवेदनशील मामले पर गंभीरता से चर्चा नहीं हुई। पुलिस और प्रशासन से कानून के अनुसार एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट ली जानी चाहिए।"

मानवाधिकार आयोग ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के अनुसार, प्रारंभिक रूप से पीड़िता के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आयोग ने 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया है।

आयोग ने कहा, "रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वह लेह के उपायुक्त (डीसी) और लेह, लद्दाख के एसएसपी/डीआईजी को नोटिस जारी करें और शिकायत में लगाये गये आरोपों की जांच कराएं। सात दिन में आयोग के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।"

भाषा जोहेब सुरेश

सुरेश

यह खबर 'भाषा' न्यूज़ एजेंसी से 'ऑटो-फीड' द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.